

भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2519
दिनांक 10 अगस्त 2026

कच्चे तेल एवं गैस की आपूर्ति संबंधी भू-राजनीतिक व्यवधानों तथा पारवहन संबंधी जोखिमों का प्रभाव

2519 श्री मुकुल वासनिक:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने हाल के वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों तथा समुद्री पारवहन संबंधी जोखिमों का भारत की कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस की आपूर्ति श्रृंखलाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई आकलन किया है;
- (ख) यदि हां, तो विशेष रूप से प्रमुख समुद्री नौवहन मार्गों तथा सामरिक संकरे समुद्री मार्गों (चोक प्वाइंट्स) से संबंधित चिह्नित कमजोरियों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) सरकार द्वारा उक्त व्यवधानों के प्रभाव को कम करने के लिए आयात स्रोतों में विविधीकरण तथा वैकल्पिक पारवहन मार्गों को सुरक्षित करने हेतु उठाए गए विशिष्ट सामरिक एवं निवारक कदम क्या-क्या हैं; और
- (घ) भारत के सामरिक पेट्रोलियम भंडार (आईएसपीआरएल) की वर्तमान स्थिति एवं भंडारण क्षमता क्या है तथा दीर्घकालिक आपूर्ति संबंधी बाधाओं के समाधान हेतु इनके तत्काल विस्तार की क्या योजना है?

उत्तर
**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)**

(क) से (घ) ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने और आपूर्ति जोखिमों को कम करने के लिए, सरकार निरंतर निगरानी करती है और उन खतरों का आकलन करती है, जो ऊर्जा आपूर्ति में संभावित व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं।

ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने और आपूर्ति जोखिमों को न्यूनतम करने हेतु भारत ने अपने कच्चे तेल के स्रोत पोर्टफोलियो को उल्लेखनीय रूप से विविधीकृत किया है, जो 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक विस्तारित हुआ है। इसी प्रकार, एलएनजी की आपूर्ति भी 6 देशों से बढ़कर 15 देशों तक विस्तारित हुई है। इस विविधीकरण से किसी एक देश, क्षेत्र अथवा पारगमन मार्ग पर निर्भरता कम हुई है तथा भारत की आपूर्ति व्यवधानों और बाज़ार अस्थिरता को प्रबंधित करने की क्षमता में वृद्धि हुई है। सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस कंपनियों तथा अन्य हितधारकों के परामर्श से, वैश्विक आपूर्ति परिस्थितियों का निरंतर आकलन करती है और कच्चे तेल, एलएनजी तथा पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त कार्रवाई करती है।

सरकार ने 'इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल)' नामक एक विशेष कंपनी के माध्यम से, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में 3 स्थानों पर कुल 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) क्षमता वाले सामरिक पेट्रोलियम भंडार (एसपीआर) सुविधाओं की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने ओडिशा और कर्नाटक में कुल 6.5 एमएमटी भंडारण क्षमता वाली दो अतिरिक्त वाणिज्यिक-सह-सामरिक पेट्रोलियम भंडार सुविधाओं की स्थापना को भी स्वीकृति दी है। इसके अतिरिक्त, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) कर्नाटक में 1.75 एमएमटी क्षमता वाली एक सामरिक पेट्रोलियम भंडार सुविधा का विकास कर रहा है।
